NeGP नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान **National e-Governance Plan**

पिछले कुछ वर्षों में, विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा ई-सरकार के युग में प्रवेश करने के लिए बड़ी संख्या में पहल की गई हैं। सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार करने और उन तक पहुँचने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई स्तरों पर निरंतर प्रयास किए गए हैं।
भारत में ई-गवर्नेंस सरकारी विभागों के कम्प्यूटरीकरण से लेकर उन प्रयासो तक तेजी से विकसित हुआ है, शासकीय नीतियों और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं वितरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संबंधित है । जैसे

- नागरिक केंद्रित कार्यान्वयन,
- , सेवा उन्मुखीकरण
- और पारदर्शिता।

ई-गवर्नेंस प्रयासो ने देश की प्रगतिशील ई-गवर्नेंस रणनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर सरकार के विभिन्न अंगों में ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन को गति देने के लिए इस धारणा का पर्याप्त संज्ञान लिया गया कि एक वृहद कार्यक्रम दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है, जो हम्यक दृष्टि और तकनीकि रणनीति द्वारा निर्देशित हो।
इस दृष्टिकोण में शामिल है -
मूल और सहायक बुनियादी ढांचे को साझा करने और सुलभ बनाने ।
मानकों के माध्यम से अंतर-संचालनीयता को सक्षम बनाने और नागरिकों को सरकार तथा सरकारी नीतियों योजनाओं के बारे में के बारे में एक सहज दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के माध्यम से मिथलेश उत्तरदाई और कल्याणकारी तरीके से क्षमता निर्माण में की सक्षम बनाना है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी)

- यह देश भर में ई-गवर्नेंस के प्रयासो का समग्र दृष्टिकोण लेती है, उन्हें एक सामूहिक दृष्टि, एक साझाकरण में एकीकृत करती है।
- इस विचार के इर्द-गिर्द, दूर-दराज के गाँवों तक पहुँचने वाला एक विशाल देशव्यापी बुनियादी ढांचा विकसित हो रहा है ।
- इंटरनेट पर आसान, विश्वसनीय पहुँच को सक्षम करने के लिए रिकॉर्ड का बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण हो रहा है।
- अंतिम उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं को नागरिकों के घर के करीब लाना है, जैसा कि एनईजीपी के विजन स्टेटमेंट में व्यक्त किया गया है।
- "सार्वभौम सेवा वितरण केंद्रों के माध्यम से आम आदमी को उसके इलाके में सभी सरकारी सेवाएं सुलभ कराएं और आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सस्ती कीमत पर ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना ।
- सरकार ने 18 मई, 2006 को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) को मंजूरी दी ।
- इसमें 27 मिशन मोड परियोजनाएं और 8 घटक शामिल थे।
- सूची बनाने के लिए वर्ष 2011 में 4 परियोजनाओं - स्वास्थ्य**,** शिक्षा**,** पीडीएस और पोस्ट की शुरुआत की गई थी।
- 31 मिशन मोड परियोजनाएं **MMP** प्रारम्भ की गयीं । सरकार ने एनईजीपी के विजन, दृष्टिकोण, रणनीति, प्रमुख घटकों, कार्यान्वयन पद्धति और प्रबंधन संरचना को मंजूरी दे दी है।
- ई-गवर्नेंस को समग्र रूप से बढ़ावा देने के लिए, कोर और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए विभिन्न नीतिगत पहल और परियोजनाएं शुरू की गई हैं।
- राज्य डेटा केंद्र **(SDCs**) ,
- स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क **(SWAN**) ,
- कॉमन सर्विस सेंटर **(CSCs**)
- मिडलवेयर गेटवे यानी नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे **(NSDG) ,**
- स्टेट ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे **(NSDG**) मोबाइल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे **(MSDG).** महत्वपूर्ण सहायक घटकों में सुरक्षा, मानव संसाधन, नागरिक जुड़ाव, सोशल मीडिया के साथ-साथ

मेटाडेटा, इंटरऑपरेबिलिटी, एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, सूचना सुरक्षा आदि से संबंधित मानक नीतियां और दिशानिर्देश शामिल हैं।

- नवीन प्रयासो में प्रमाणीकरण के लिए एक ढांचा शामिल है, अर्थात ई-प्रमाण और जीआई क्लाउड , एक पहल जो ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ सुनिश्चित करती है ।